

ढई साल में 42 मेगा फूड पार्क हो जाएंगे चालू : साध्वी निरंजन ज्योति

खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री ने कहा, अब तक छह मेगा फूड पार्क हो चुके शुरू

नई दिल्ली | देश में 2019 तक 42 मेगा फूड पार्क चालू हो जाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। इन फूड पार्क में खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण होने से किसानों की आय बढ़ सकेगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने मंगलवार को यह विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, 'एनडीए सरकार के आने के पहले देश में सिर्फ दो मेगा फूड पार्क काम कर रहे थे। एनडीए सरकार ने कुल 42 मेगा फूड पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है। वर्ष 2014 से अब तक छह मेगा फूड पार्क शुरू हो चुके हैं। दो-तीन माह में चार और शुरू हो जाएंगे।' वे उद्योग संगठन एसोचैम के 'राष्ट्रीय कोल्ड चैन सम्मेलन' में बोल रही थीं। उन्होंने कहा, 'कृषि और प्रसंस्करण क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार देने की

कृषि उपज का महज 2% प्रसंस्करण होना चिंताजनक : योकोयामा

इस मौके पर एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंटी डायरेक्टर केनिची योकोयामा ने कहा, 'फसलों के तैयार होने के बाद बड़े पैमाने पर उनका नष्ट होना और कुल कृषि उपज का महज दो फीसदी प्रसंस्करण होना चिंताजनक है। देश में ज्यादातर किसान छोटे और सीमांत श्रेणी के हैं। सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना चाहती है। इसमें कोल्ड चैन योजना काफी मददगार साबित हो सकती है।' उन्होंने खाने-पीने की जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए बिजली और सड़क संपर्क के क्षेत्र में निवेश की जरूरत पर जोर दिया।

संभावना है। इसके मद्देनजर सरकार कम पूंजी में छोटे स्तर पर कोल्ड चैन योजना को लागू कर रही है। बड़ी कोल्ड चैन की स्थापना में 25 से 30 करोड़ रुपए की लागत आती है इससे कम पूंजी वाले लोग इस व्यवसाय में नहीं आ पाते हैं।' छोटी कोल्ड चैन की स्थापना में 50% तक सब्सिडी |निरंजन ज्योति ने कहा, 'किसान समूह

छोटे स्तर पर कोल्ड चैन की स्थापना करें और वहां प्रसंस्करण इकाई की भी स्थापना करें तो सरकार उन्हें संपदा योजना के तहत 50% तक सब्सिडी देती है। यह 1.5 से 5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। संपदा योजना के तहत 6,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इसे 2020 तक खर्च किया जाएगा।'

42 मेगा फूड पार्क 2019 तक खुलेंगे

नई दिल्ली। देश में 2019 तक 42 मेगा फूड पार्क चालू हो जाएंगे, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यापक पैमाने पर खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किया जा सकेगा। साथ ही इससे किसानों की आय भी बढ़े सकेगी।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एसोचैम की ओर से मंगलवार को यहां आयोजित राष्ट्रीय कोल्ड चेन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के आने के पहले केवल दो मेगा फूड पार्क कार्य कर रहे थे।

नॉन फूड रिटेल में 100 फीसद एफडीआइ पर हो रहा विचार

नई दिल्ली, आइएनएस : फूड प्रोसेसिंग उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि सरकार मल्टी ब्रांड रिटेल पॉलिसी के तहत नॉन फूड आयटमों में भी 100 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने पर विचार कर रही है। सरकार ने पहले प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट की रिटेलिंग में 100 फीसद एफडीआइ की अनुमति दी थी।

बादल ने कहा कि पिछले साल प्रोसेस्ड फूड की रिटेल ट्रेडिंग में एफडीआइ को अनुमति के बाद पिछले साल जून के बाद एफडीआइ में 40 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। इससे कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि यह नीतिगत बदलाव प्रोत्साहित करने वाला रहा है। अमेजन अगले कुछ वर्षों में 3500 करोड़ रुपये निवेश करने जा रही है। पिछले साल सरकार ने घरेलू उत्पादित प्रोसेस्ड फूड की रिटेलिंग में 100 फीसद

एफडीआइ की अनुमति दी थी। मंत्री ने संकेत दिया है कि अब सरकार नॉन फूड आयटम की रिटेलिंग में भी अनुमति देने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि वह जब भी विदेश गईं, उन्हें कंपनियों ने बताया कि उनके पास ऐसे मॉडल मौजूद हैं, जिन्हें किसी भी देश में लागू किया जा सकता है।

तीन में चार मेगा फूड पार्क चालू होंगे : नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने कहा है कि वह फूड प्रोसेसिंग उद्योग के विकास में तेजी लाने को काम कर रही है। अगले तीन माह में चार पार्क चालू हो जाएंगे। फूड प्रोसेसिंग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एसोचैम के कार्यक्रम में कहा कि उद्योग फूड प्रोसेसिंग में दिलचस्पी लेने लगा है। सरकार ने कोल्ड चैन प्रोजेक्टों के लिए 300 प्रस्ताव मिले हैं। 2014 के बाद तीन साल में छह मेगा फूड पार्क चालू हो चुके हैं।

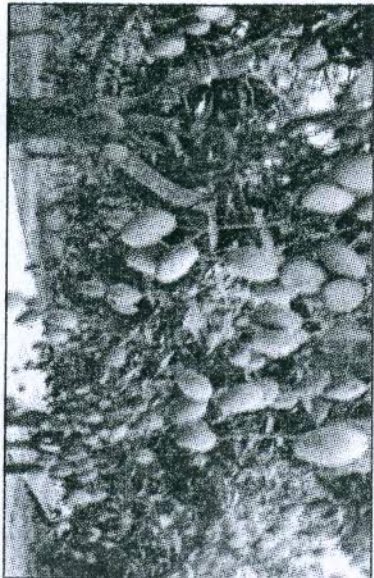
इस बार द. कोरिया को आम निर्यात पर जोर

■ आम का प्रमुख बाजार है द. कोरिया ■ वहां निर्यातकों को मिलते हैं अच्छे दाम

■ नई दिल्ली ।

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण निर्यात विकास निगम (एपीडा) के अध्यक्ष डीके सिंह ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के मद्देनजर इस वर्ष दक्षिण कोरिया को अधिक से अधिक आम के निर्यात का प्रयास किया जा रहा है।

श्री सिंह ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में दक्षिण कोरिया को आम का प्रीमियम बाजार बताते हुए कहा कि वहां गुणवत्तापूर्ण आम की मांग है। यहां दाग रहित एक आकार के आम की बहुत



अधिक मांग है। पिछले साल कोरिया में आम का निर्यात किया गया था। इस वर्ष

था। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, खाड़ी के देशों तथा कई अन्य देशों

कोरिया को निर्यात किए जाने वाले आम की गुणवत्ता और उसके पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया के आम बाजार पर थाईलैंड और फिलीपींस का कब्जा

को लम्बे समय से आम का निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि आम को अधिक दिनों तक ताजा बनाए रखने के लिए उसे 15-16 डिग्री तापमान पर रखना होता है जो एक चुनौती है।

श्री सिंह ने कहा कि देश के कृषि योग्य जमीन के 11.5 प्रतिशत क्षेत्र में बागवानी फसलों को लगाया जाता है जो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस वर्ष अंगूर के निर्यात में 37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है लेकिन अमरूद और पपीता के निर्यात के क्षेत्र कुछ खास नहीं हुआ है। ■ वार्ता

द. कोरिया में आम निर्यात पर जोर

नई दिल्ली, 30 मई (एजेंसी): कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण निर्यात विकास अथारिटी (एपेडा) के अध्यक्ष डी.के. सिंह ने कहा कि किसानों की आय में वृद्धि के मद्देनजर इस वर्ष दक्षिण कोरिया को अधिक से अधिक आम के निर्यात का प्रयास किया जा रहा है।

श्री सिंह ने आज यहां एसोचैम की ओर से आयोजित राष्ट्रीय कोल्ड चेन सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए दक्षिण कोरिया को आम का प्रीमियम बाजार बताते हुए कहा कि वहां गुणवत्तापूर्ण आम की मांग है। यहां दाग रहित एक आकार के आम की बहुत अधिक मांग है। पिछले साल कोरिया में आम का निर्यात किया गया था। इस वर्ष कोरिया को निर्यात किए जाने वाले आम की गुणवत्ता और उसके पैकेजिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया



के आम बाजार पर थाईलैंड और फिलीपींस का कब्जा था। अमेरिका ब्रिटेन, जापान, आस्ट्रेलिया, कनाडा, खाड़ी के देशों तथा कई अन्य देशों को लम्बे समय से आम का निर्यात करता है।

भारत फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर

उन्होंने कहा कि भारत विश्व में दूध उत्पादन और खपत के मामले में पहले स्थान पर है और फलों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर। इन क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण उत्पादों से किसानों

को न केवल बेहतर मूल्य मिलेगा बल्कि निर्यात के अधिक अवसर मिलेंगे।

2019 तक 42 मैगा फूड पार्क हो जाएंगे चालू

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देश में 2019 तक 42 मैगा फूड पार्क चालू हो जाएंगे जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा और व्यापक पैमाने पर खाद्य पदार्थों का प्रसंस्करण किया जा सकेगा जिससे किसानों की आय बढ़ सकेगी। उन्होंने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने आने के पहले केवल 2 मैगा फूड पार्क कार्य कर रहे थे। किसानों की आय में वृद्धि और कृषि उत्पादों को जल्द नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार ने कुल 42 मैगा फूड पार्कों की स्थापना का निर्णय लिया है।